VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 31 AUG 2022 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	Dinesh Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	58740
Center	Mukherjee Nagar	Date	31/08/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद से तात्पर्य है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना तथा उनसे विचलित नहीं होना।

यह 'संवैधानिक नैतिकता' की तरफ जाने का रास्ता है।

जैसे:- शक्तियों का पृथक्करण पर जोर देते हुए। न्यायिक अतिरेक (overreach) से बचना।

भारतीय संविधान में उपबन्ध

(1) प्रस्तावना - संविधान की आत्मा है। सामाजिक - आर्थिक - न्याय प्राप्त करने पर जोर देती है। इसी तरह विभिन्न स्वतंत्रताओं (विचार, अभिव्यक्ति आदि) पर जोर।

(2) मूल अधिकार - राज्य नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु। इनका संरक्षण सुनिश्चित करे। (अनु. 13)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) DPSP - राज्य को निर्देश है कि वह इनको प्राप्त करने का प्रयास करे।
जैसे - स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण

(4) न्यायिक समीक्षा - न्यायपालिका का दायित्व है कि 'संवैधानिक सर्वोच्चता' बनाए रखे तथा अनुच्छेद 32 व अनु. 226 के माध्यम से 'गैर-संवैधानिक' विधियों व कार्यों को अवैध घोषित करे।

(5) शक्ति का स्रोत - संविधान ही शक्ति का स्रोत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधानमंडल इसी से शक्ति प्राप्त करते है।

(6) संवैधानिक संशोधन - इसमे संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है ताकि सर्वोच्चता बनी रहे।

(7) मूल कर्तव्य - प्रथम कर्तव्य यही है कि संविधान के आदर्शों व संस्थाओं का सम्मान करे

इस प्रकार ये उपबंध संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए संविधानवाद पर जोर देते है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.
(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत CCI की स्थापना की गई जो एक स्वच्छ, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

लाइसेंस राज से अनुकूल नियामकीय परिवेश

- MRTP Act की समाप्ति यद्यपि हो गई थी परन्तु अनुकूल परिवेश नहीं था। CCI ने इसे सक्षम बनाया।
- छोटे उद्यमों को बराबरी का अवसर दिया
- गलत गतिविधियों पर रोक लगाते हुए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दिया
- व्यापार की गलत प्रथाओं पर जुर्माना लगाया।
- अब सरकार, नियंत्रक से नियामक की भूमिका में आई।
- अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त हो गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपभोक्ता कल्याण

- प्रतिस्पर्धा सकारात्मक है तो दक्षता बढ़ती है। इससे सामान सस्ता व सुलभ होता है। अतः उपभोक्ता के लिए हितकर है।
- एकाधिकार समाप्त होता है तो विक्रेता कई होते है। इससे 'विकल्प' बढ़ते है। अतः गुणवत्ता युक्त उत्पाद की ही बिक्री होती है।
  जैसे- BSNL से निजी कंपनियों की तरफ उपभोक्ता स्थानांतरण
- सरकार ने लघु उद्योगों, MSME को प्रोत्साहन दिया। इससे स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिला।

अतः CCI ने एक समान व्यापार का स्तर उपलब्ध कराते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' भी बढ़ाया तथा साथ ही 'उपभोक्ता कल्याण' में भी वृद्धि की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.

(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारत में लगभग 5 करोड़ मामले न्यायालयों मे लंबित है। इस स्थिति मे ऑनलाईन सेवा प्रदायगी मील का पत्थर है।

विभिन्न पहले

(1) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
– उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय मे विभिन्न मामले 'ऑनलाईन' सुने जाते है जैसे - COVID में ऑनलाईन सुनवाई

(2) SUPACE प्रणाली – सर्वोच्च न्यायालय मे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' आधारित प्रणाली है। इससे दक्षता बढ़ी है

(3) मुकदमों की डिटेल वेबसाईट पर
– सभी मुकदमों की सुनवाई व अगली तारीख ऑनलाईन उपलब्ध है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) e-court – इसके माध्यम से जिला अदालतों सहित सभी न्यायालयों का ब्यौरा एक स्थान पर उपलब्ध है

(5) e-प्रिजन – न्यायालय के आदेश अब तुरंत। जेल अधिकारियों तक पहुंच सकते है।

इसी तरह हार्ड-कोर अपराधियों के मामले में 'जेल से सुनवाई' करवाना तथा लोक-अदालतों व ग्राम-न्यायालयों का ब्यौरा पहले ही वेबसाईट पर उपलब्ध कराना आदि प्रयास शामिल है

इससे न्यायिक सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से इसने मूल अधिकार ग्रहण किए है परन्तु उनमे आवश्यकतानुसार संशोधन के पश्चात् ही समावेश किया है।

बिल ऑफ राइट्स व मूल अधिकार मे समानता :-

→ दोनो नागरिकों को 'राज्य' के विरुद्ध प्राप्त है

⇒ 'सर्वांगीण विकास' पर जोर देते है

⇒ 'राजनीतिक लोकतंत्र' को मजबूत करते है

⇒ 'न्यायिक संरक्षण' प्राप्त है।

⇒ सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के प्राप्त है

⇒ 'युक्तियुक्त निर्बंधन'. लागू है

⇒ ये सभी अधिकार 'एक प्रगतिशील समाज' के निर्माण की दिशा मे है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंतर

बिल ऑफ राईट्स	मूल अधिकार
(1) कम विस्तृत है।	• संविधान में विस्तार से लिखा है
(2). न्यायिक व्याख्याओं से आए हैं	• मूल संविधान में वर्णित हैं
(3) इसमें 'हथियार रखना' सहित अधिकार भी शामिल हैं	• भारत में यह मूल अधिकार नहीं है
(4) ~~उच्च न्यायालय~~ इसमें न्यायिक व्याख्याओं का scope ज्यादा है।	• ये पहले से विस्तृत हैं तो न्यायिक व्याख्या का scope कम है

अतः भारतीय मूल अधिकार ज्यादा विस्तृत व प्रभावी हैं जो भारतीय विविधतापूर्ण समाज के लिए आवश्यक भी है। सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण है

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

FRA. 2006 वनवासियों एवं ग्राम-सभाओं को सशक्त करते हुए । जोइंट-क्रियान्वयन पर जोर देता है।

कार्यान्वयन धीमा व निष्प्रभावी

(1) लघु वनोत्पादों (MFP) का वास्तविक लाभ वनवासियों को प्राप्त नहीं

(2) ग्राम-सभा की अनुमति सिर्फ कागजों में। जैसे - हसदेव जंगल (छत्तीसगढ़) के विरोध के बावजूद कोयला खनन।

(3) विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन।

(4) PESA एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है।

(5) MESA एक्ट अब तक नहीं लाया गया। इससे शहरी जंगल में रहने वाले आदिवासियों को कम स्वायत्तता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) चूंकि यह कानून मानव-पर्यावरण सह-अस्तित्व पर जोर देता है जबकि पर्यावरणीय मंजूरी में इसे दरकिनार किया जाता है

(7) सतत विकास की अवधारणा को सही से लागू नहीं करना।
जैसे- मुंबई में 'आरे फॉरेस्ट' मामला

समाधान

↳ 'Letter & spirit' में कानून लागू हो
↳ परंपरागत ज्ञान का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में हो (आदिवासियों के)
↳ ग्राम-सभा मजबूत हो।
↳ सोशल ऑडिट सभी योजनाओं का हो

अतः वन-अधिकार कानून 2006 का क्रियान्वयन भारत में पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा, वहीं आदिवासियों में भी अलगाव प्रवृति नहीं होगी।

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सामाजिक कार्यों हेतु खर्च करने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने हेतु UK की तर्ज पर भारत में भी 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' शुरू किया गया है।

सृजन के पीछे निहित तर्क

→ सामाजिक पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना
→ उन प्रयासों की पहचान जो सामाजिक कार्यों में वृद्धि करते हैं
→ सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन (समाधान)
→ कंपनियों की समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा
→ गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन में सहायक
→ ब्रांड वैल्यू बढ़ाना ताकि समाज में स्वीकृति ज्यादा हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन

- सामाजिक कार्यों में खर्च करने वाली कंपनियों की 'प्रतिष्ठा' समाज में ज्यादा है, इस कारण निवेश ज्यादा आकर्षक जैसे - विप्रो, टाटा।
- कंपनी की विज्ञापन लागत का प्रयोग वह सामाजिक निवेश में कर सकती है इससे समाज में स्वतः प्रचार होगा।
- अब लोग लाभ-हानि के साथ-साथ समाज व पर्यावरणीय प्रभावों को भी महत्व देने लगे हैं। इस कारण कंपनियां इस दिशा में निवेश करना चाहेंगी।

अतः यह एक सकारात्मक कदम है जो गुणवत्तापूर्वक निवेश को बढ़ाएगा तथा अन्य कंपनियों को सामाजिक निवेश हेतु प्रोत्साहित करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ NDHM स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी विज्ञान का प्रयोग करके आमजन तक रक्षित प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है

NDHM

↳ एक हैल्थ-प्रोफाईल बनाई जाएगी।

↳ मेडिकल हिस्ट्री- रिकॉर्ड दर्ज होंगे।

↳ डिजी-लॉकर की तरह ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा।

↳ सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों को जोड़ा जाएगा।

↳ डेटा की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा

↳ सभी लोगों के डेटा से एक विश्लेषण करना आसान होगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्रान्ति की क्षमता

↳ चिकित्सक पुरानी बीमारियों से तुरंत परिचित हो जाएगा।

↳ बेहतर उपचार प्राप्त होगा

↳ बीमारी का ट्रेंड पकड़ना आसान

↳ पुराने रिकॉर्ड संभालकर रखने से छुटकारा।

↳ पूरा स्वास्थ्य-तंत्र डिजिटल हो जाएगा।

अतः NDHM हैल्थ सेक्टर में एक शांति लाकर डिजिटल क्रान्ति के लाभों से स्वास्थ्य क्षेत्र को उन्नत बनाएगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है इसमें राज्य व केन्द्र सरकार के साथ ही निजी क्षेत्र भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्यता

- सरकार सभी तक शिक्षा की पहुँच अकेली नहीं कर सकती।
- गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र जरूरी है
- अनुसंधानात्मक विकास हेतु उच्च शिक्षा में सरकार अकेले वित्तीय बोझ नहीं उठा पाती है
- NEP. 2020 द्वारा प्रदत्त GDP के 6% से भी कम सरकारी खर्च।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

• 65% युवा आबादी की कौशल शिक्षा कॉलेज शिक्षा बिना निजी क्षेत्र कठिन है

उपयुक्त मुद्दे

(1) शिक्षा का व्यावसायीकरण
– महंगे व उच्च प्रतिष्ठा वाले स्कूलों का निर्माण करके व्यावसायीकरण हो गया है

(2) गरीब की पहुंच से बाहर – गरीब व्यक्ति महंगे स्कूल-कॉलेज में अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाता।

(3) RTE Act-2009 का क्रियान्वयन
– निजी संस्थान इसकी पालना ढंग से नहीं कर रहे।

इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार व निजी दोनों ही सेक्टरों की भागीदारी रहनी चाहिए। साथ ही 'दिल्ली-मॉडल' की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में व्यापक सुधार हो ताकि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़-लिख सकें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. **(150 words) 10**

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

मध्य एशिया भारत के लिए यूरोप का गेट-वे है तथा सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

मध्य एशिया – कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान।

महत्व

(1) यूरेनियम आपूर्ति – कजाकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति होती है

(2) विदेशी सैन्य अड्डा – 'फरखोर' सैन्य अड्डा मध्य एशिया में है

(3) TAPI पाईप – गैस-पाईप लाईन से भारत की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ती

(4) INSTC – यूरोप व रूस तक कनेक्टिविटी का रास्ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

(1) प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी नहीं

→ चाबहार बंदरगाह का माध्यम है
→ दूरी ज्यादा है।

(2) चीनी प्रभाव - चीन वहाँ भी अपना प्रभाव जमा रहा है

(3) भाषा - इस कारण People to People Contact कम है

(4) व्यापार कम - द्विपक्षीय व्यापार कम है

यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ बेहतर संबंध भारत को यूरेशियाई क्षेत्र एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से लाभ प्रदान करेंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारतीय डायस्पोरा विश्व में 110 मिलियन है जो अपनी प्रभावी भूमिका से भारत के विदेशी संबंधो को उठाने में सहायक है।

आत्म-निर्भर भारत हेतु भूमिका

(1) निवेश - भारतीय मूल के OCI भारत में निवेश करके प्रत्यक्षतः सहायता दे सकते

(2) नीति-निर्माण - विदेशों में अपनी प्रभावी पहुँच से द्विपक्षीय संबंधो में मजबूती लाकर लाभ पहुँचाना।

जैसे - 2005 की US-India न्यूक्लियर समझौता में डायस्पोरा की बड़ी भूमिका

(3) भारतीय वस्तुओं की माँग

- भारतीय डायस्पोरा विदेशों में भारतीय वस्तुओं की माँग करता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां

- वोटिंग व दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं।
- अरब देशों का डायस्पोरा कफाला प्रणाली नियोक्ता प्रणाली के शोषण का शिकार
- निवेश कम मात्रा में।

भारत को डायस्पोरा को 'प्रवासी भारतीय दिवस' जैसे प्रयासों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा भारत से जोड़ना चाहिए ताकि विदेशी पूंजी, तकनीक भारत में आकर 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा दे सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74 वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को 'संवैधानिक दर्जा' दिया गया तथा अनुसूची - XII में शामिल किया।

संशोधन के परिणाम

सकारात्मक — सहभागी लोकतंत्र की स्थापना लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई

→ स्थानीय विषयों का समाधान आसानी से जैसे - पानी, स्वच्छता आदि

→ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है

→ वंचित वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण

नकारात्मक — धन-बल, बाहुबल का प्रभुत्व बना हुआ है

→ आम नागरिक का चुनाव लड़ना व जीतना कठिन है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ वित्त का अभाव है।

→ चेयरमैन पति, पार्षद-पति जैसी अवधारणाए है।

→ चुनाव में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि प्रमुख तत्व है।

विकेन्द्रीकरण हेतु दूसरी पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता :-

(1) वार्ड - समितियों को सशक्त किया जाना जरूरी है।

(2) स्वयं के वित्त- स्रोतों का होना जरूरी है।

(3) 18 विषयों पर काम करने हेतु कार्मिक, विशेषज्ञता, धन का अभाव है

(4) पार्टी का शासन भावना मजबूत है

(5) भ्रष्टाचार बहुत है

(6) सोशल ऑडिट कमजोर है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान

- म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्त जुटाना।
- 'सोशल ऑडिट' की प्रभावी अनुपालना।
- वार्ड-पार्षदों को उचित प्रशिक्षण देकर जागरूक करना व सशक्त बनाना।
- 'राज्य वित्त आयोग' की अनुशंसाओं पर सरकारें ध्यान दें।
- 'जिला आयोजना समिति' (अनु. 243(ZD)) में सभी की उपस्थिति व प्रभावी भूमिका सुनिश्चित हो।

अतः सुधार 2.0 नगरीय निकायों को सशक्त, आत्मनिर्भर व प्रगतिशील बनाकर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करेंगे। इससे लोकतंत्र की जड़े और गहरी होती जाएंगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

भारत में प्रथम संविधान संशोधन - 1951 के माध्यम से नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया।

प्रावधान - 9वीं अनुसूची के रखे विधि 'न्यायिक समीक्षा' से बाहर है।

संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी

. यदि 9वीं अनुसूची में विधि है तो चूंकि 'न्यायिक समीक्षा' से बाहर है इसे 'संविधान की Check & Balance' भावना का उल्लंघन होता है अर्थात् संविधान की कसौटी पर विधि को परखने की शक्ति कम होने का तात्पर्य है कि 'संविधान की सर्वोच्चता' को

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समर्थोट करना है।

परन्तु 'आई. आर. कोहिल्हो' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात की विधि की 'न्यायिक समीक्षा' की जा सकती है चाहे वे 9वीं अनुसूची में रखी जाए।

चूंकि 'केशवानंद भारती मामले 1973' में 'बेसिक स्ट्रक्चर' का सिद्धांत दिया गया तथा 'न्यायिक समीक्षा' स्वयं एक 'बेसिक स्ट्रक्चर' है। अतः इस बाद के बाद की विधियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

अतः इस फैसले ने (I.R. Coelho)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

'संविधान की सर्वोच्चता' को पुनः बनाए रखने का प्रयास किया है

अतः बेहतर यही है कि विधियाँ 'न्यायिक समीक्षा' के दायरे में ही रहे ताकि 'संसद का आधिपत्य' न होकर 'संविधान की सर्वोच्चता' प्रभावी रहे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

भारत 'राज्यों का संघ' है। इसे विभिन्न राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया है अपितु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत को विभिन्न इकाईयों मे बाँटा गया है।

असममिति के कारण भारत में 'one size fits for all' सिद्धांत पर कार्य नहीं होता है बल्कि विविध मांगो के अनुसार आवश्यक सुधार किए जाते है।

जैसे - नए राज्यों का गठन
- राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
- विशेष राज्य का दर्जा देना आदि

इस विशेषता के कारण भारत में 'विविधता में एकता' को बनाए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थान आकार हुआ है।

जैसे:

(1) राज्यों का पुर्नगठन

- राज्य पुर्नगठन अधिनियम -1956 के अनुसार भाषाई आधार, प्रशासनिक आधार पर नए राज्य बने। जैसे -14 राज्य, 6 संघ क्षेत्र। आंध्रप्रदेश, केरल।

(2) सीमाओं के परिवर्तन

- असम से मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि का पुर्नगठन

(3) विकास के नाम पर

2014 में तेलंगाना का गठन।

(4) शासन-व्यवस्था तथा विकास

सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखण्ड का गठन।

(5) राष्ट्रीय सुरक्षा

J&K को संघ राज्य क्षेत्र बना, लद्दाख को अलग किया)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

असमरूपिता के कारण ही विविध मांगों का समायोजन हुआ है क्योंकि राज्यों को भू-भाग की संप्रभुता की गारंटी नहीं दी गई है। इसी कारण भारतीय संघ को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा गया है।

अतः असमरूपिता भारत जैसे बहु-भाषी, बहु-धार्मिक, भौगोलिक विषमताएं युक्त देश के लिए एक आवश्यक उपागम है जो राष्ट्र की एकता व अखण्डता बनाने के साथ ही विकास पर जोर देता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

भारत में केन्द्र सरकार मे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त-आयोग का गठन होता है वहीं राज्यों में 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन के अनुसार । राज्य वित्त आयोग' का गठन होता है

राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने मे

प्रभावी रहे है

↳ पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों को धन का आवंटन होता है

↳ अनुदान भी मिलती है

↳ केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुसार भी सिफारिश होती है

↳ विभिन्न विषयों पर कार्य करने

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हेतु (पंचायत - 29, शहर - 18) राज्य की संचित निधि से धन का आवंटन।

प्रभावी नहीं रहे हैं

↳ बहुत से राज्य इनका गठन ही समय पर नहीं करते हैं (हर 5 वर्ष पर) जैसे - पश्चिमी बंगाल

↳ इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं

↳ ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को समय पर धन नहीं मिलता है

↳ इन निकायों के स्वयं के भी वित्त स्रोत नहीं हैं

↳ ये निकाय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर बहुत कम वित्त ही प्राप्त कर पाते हैं। ~~जो~~

इस तरह 'राजकोषीय संघवाद' के प्रतिकूल ही काम होता हुआ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतीत होता है।

समाधान

- नियमित राज्य वित्त आयोग का गठन।
- शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटन
- वित्तीय संरचना पारदर्शी व मुक्त हो।

अतः सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोगों द्वारा वित्तीय सहायता व सरकार द्वारा अनुपालन जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India. **(250 words) 15**

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

नौकरशाही के आकार में कमी की बजाय उसे जनोन्मुखी बनाकर ज्यादा बेहतर कार्य किया जा सकता है।

समग्र आकार में कमी

- DoPT मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार भारत में निर्धारित संख्या के तीन-चौथाई ही नौकरशाह कार्यरत है अर्थात् इनकी संख्या में कमी है।
- हर वर्ष UPSC द्वारा भर्ती में पोजीशन की संख्या में भी कमी दिखाई दे रही है
- अधीनस्थ स्तरों पर भी कर्मचारियों की कमी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल सेवाओं में सुधार

- कमी को पूरा करने के लिए 'Lateral Entry' के माध्यम से उच्च पदों पर नियुक्तियाँ होने लगी है।
- इससे दक्षता, निजी क्षेत्र का अनुभव आदि का लाभ मिलने की उम्मीद है

नौकरशाही का आकार कम करना उपयुक्त विचार

हाँ – इससे लागत कम होती है
- मशीनीकरण व तकनीकी को बढ़ावा देकर बेहतर दक्षता पा सकते है
- निर्णय प्रक्रिया तीव्र हो सकती है
- 'लेटरल एन्ट्री' से निजी क्षेत्र का लाभ ले सकते है।

नहीं – नौकरशाह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुने हुए योग्य लोग होते है। इनसे प्रशासन बेहतर बनता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- कम संख्या मे 'कार्य-बोझ' बढता है इसलिए उत्पादकता कम होती है, तनाव बढता है
- सरकारी निर्णय समय पर नहीं हो पाते हैं।

समाधान

- संख्या कम करने की बजाय उन्हें प्रो-एक्टिव, अधिक लोकतांत्रिक, तकनीकी दक्ष बनाए जाने पर जोर दिया जाए
- उनमे नैतिक मूल्यों का विकास हो
- 'मिशन कर्मयोगी' का क्रियान्वयन सही से हो
- 'बासवान कमेटी', खन्ना समिति, होता समिति की सिफारिशें व 2nd ARC के अनुसार Rule Based से Role Based तथा 'नियंत्रण से नियामक' तथा 'Regulator से Facilitator' की भूमिका मे लाकर एक दक्ष व प्रभावी प्रशासन प्राप्त किया जा सकता है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो 'सर्वधर्म-समभाव' की नीति पर कार्य करता है। कुछ राज्यों जैसे- तमिलनाडु में मंदिर प्रबन्धन में सरकारी हस्तक्षेप का मामला कई जगह विरोध का कारण बना हुआ है

मंदिरों का बेहतर प्रबंधन

- मंदिर एक धार्मिक संस्थान है जहाँ बिना भेदभाव के सभी को पूजा का अधिकार है।
- परंपरागत रूप से मंदिर के चलाने का उपयोग कुछ परिवार ही कर रहे हैं। अतः 'Man-God' मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करे परन्तु 'Man-Man' मामला है तो सरकार को सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप

करना चाहिए।

अर्थात पुजारियों की नियुक्ति विविध हिन्दू- जातियों से करना एक 'प्रगतिशील' कदम माना जाएगा।

- इसके साथ ही प्रबंधन व जवाबदेहिता को बढ़ाने हेतु मंदिर की आय का प्रयोग पारदर्शी तरीके से धर्म के विकास तथा जनता की भलाई में हो।

राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दे

- अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार मूल अधिकार है। परन्तु सदाचार के रूप में राज्य को गैर-धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है

- केवल मंदिरों में हस्तक्षेप करना एक धर्मनिरपेक्ष छवि नहीं है

- हस्तक्षेप तभी हो जब आवश्यकता हो अर्थात् धोखा या गलत- प्रथाएँ प्रचलित हों।
- बदले की भावना से कोई हस्तक्षेप नहीं हो।

चूँकि वर्तमान परिदृश्य में मंदिरों की भूमिका धार्मिक क्रियाकलापों से बढ़ते हुए आर्थिक केंद्र के रूप में भी हो रही है। अतः इस स्थिति में सरकार को सभी पक्षों को साथ लेते हुए जहाँ जरूरत हो, वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा सरकार इन मामलों से दूर रहे, तो अच्छा है।

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. **(250 words) 15**

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में 'सिल्वर इकोनॉमी' में नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 8.64 वृद्ध जनसंख्या में महिलाएँ, पुरुषों से ज्यादा है।

जीवन प्रत्याशा → पुरुष – 67.4 वर्ष
→ महिला – 70.2 वर्ष

इससे स्पष्ट है कि वृद्ध जनसंख्या में नारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीती है। यही 'वृद्धावस्था का नारीकरण' है।

भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दे

(1) स्वास्थ्य – वृद्ध महिलाएँ ज्यादा सुभेद्य हैं उन्हें कम दिखाई देना, कम सुनना, हृदय संबंधी बीमारियां आदि का सामना

करना पड़ता है।

(2) अकेलापन – पुरुष प्रायः बाहर जाकर अपना समय व्यतीत कर लेते है परन्तु परंपरागत समाज मे महिलाएँ घर पर ही रहती है, इस कारण एकल परिवारों मे वे 'अकेलापन' का शिकार होती है, इससे अवसाद बढ़ता है

(3) वित्तीय सुरक्षा – वृद्धावस्था में पेंशन, बीमा, बचत आदि नहीं है तो वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है

(4) लैंगिक हिंसा – वृद्ध महिलाए 'आसान टारगेट' होती है। उनके खिलाफ लैंगिक अपराध बढ़े है (NCRB-2020)

समाधान के उपाय

(1) माता-पिता भरण-पोषण एक्ट - 2007
– बच्चों की कानून जिम्मेदारी है कि माता-पिता की सेवा करे। भरण-पोषण (10,000₹ प्रति माह तक) प्रदान करे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- LIC के माध्यम से 10 वर्ष तक 8% ब्याज दर से सामाजिक सुरक्षा।

(3) वृद्धावस्था पेंशन योजना - गरीब वृद्धों को प्रतिमाह 1000 ₹ - 1500 ₹ तक पेंशन।

(4) आयकर में छूट - 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए आयकर में पूर्णतः छूट।

(5) राष्ट्रीय वयोश्री योजना - BPL वृद्धों को शारीरिक उपकरण खरीदने में सहायता। जैसे - बैसाखी, श्रवण यंत्र।

इन सभी उपायों के साथ ही मानवीय संवेदनशीलता हो, बच्चे दादा-दादी के साथ समय व्यतीत करें तथा भावनात्मक रूप से उनका ध्यान रखे एवं उनके अनुभवों से सीख ले तो हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

भारत एक विकासशील देश है तथा 21.9% गरीब आबादी (2011) है, इसलिए व्यक्ति तथा देश दोनों ही सुभेद्यता (Vulnerablity) की स्थिति में है जो लचीलापन की माँग करते है

व्यक्तिगत लचीलेपन

→ गरीबी से बाहर आना
→ विकास करना
→ बीमारी से रक्षात्मक कवच (बीमा)
→ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना

अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता

→ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
→ विदेशी आर्थिक संकटो के प्रभावों से बचना जैसे - श्रीलंका, 2008 की बैंकिंग क्राइसिस
→ महामारी के प्रभावों से देश को बाहर निकालना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

(1) विकास को बनाए रखने के लिए

- सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा की स्थिति कोविड, आर्थिक मंदी आदि आघातों का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है

(2) सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना

- लोग बीमारी के कारण 'मध्यमवर्ग से गरीबी' में चले जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा इससे रक्षा करेगी।

(3) पर्यावरणीय खतरों से मुकाबला

- ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, तटीय क्षेत्रों से विस्थापन, बीमारियां बढ़ना, आदि से सुरक्षा हेतु।

(4) वैश्विक चुनौतियों से संरक्षण

- संरक्षणवाद, आपसी-युद्ध आदि से तभी मुकाबला कर पाएंगे जब स्वयं सशक्त है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय

~~वैश्विक स्तर~~ ५

व्यक्तिगत स्तर

→ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
→ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना।
→ सुकन्या समृद्धि खाता योजना।
→ भारत पेंशन योजना

ये सब व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्यास्थता बढाते है।

अर्थव्यवस्था में

→ आत्मनिर्भर भारत योजना
→ PLI योजना
→ नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर आदि

ये सभी उपाय अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता बढाकर विभिन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करते है

अतः भारत में व्यक्तिगत व अर्थव्यवस्था दोनो ही स्तर पर मजबूत सामाजिक सुरक्षा की स्थिति इसे आत्मनिर्भरता की स्थिति में रख सकेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss.
(250 words) 15

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

समय के अनुसार पुराने वैश्विक बहुपक्षीय संगठन अपनी प्रासंगिकता खो रहे है तथा नए संगठन मुद्दों के आधार पर बन रहे है। जैसे – QUAD, अब्राहम एकॉर्ड आदि

मुद्दे - आधारित गठबंधन की लोकप्रियता का कारण

- पुराने संगठनों की तुलना में निर्णय - प्रक्रिया त्वरित।
- पुराने संगठन के सब देशों की अपनी - अपनी प्राथमिकताए है अतः सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण है।
- विकसित देशों की प्रभाविकता पुराने संगठनों में ज्यादा है। अतः नए संगठनों की मांग स्वाभाविक है
- अपनी बात को स्पष्टतः रखा जा सकता है

बहुपक्षीय व्यवस्था की विश्वता

- पर्यावरण के मुद्दों पर।
- आतंकवाद समाप्त करने में।
- विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने में।
- मुद्दों को रोकने में (रूस-यूक्रेन युद्ध)
- चीन की विस्तारवादी नीति को संतुलित करने में।

मुद्दे-आधारित संगठनों में सहयोग।

(a) सुरक्षा - QUAD इण्डो-पेसिफिक में स्वतंत्र, मुक्त नौपरिवहन हेतु गठित।

(b) ऊर्जा सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) से सौर ऊर्जा में बढ़ावा आसान।

(c) BIMSTEC - क्षेत्रीय सहयोग व सुरक्षा हेतु दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश।

(d) कनेक्टीविटी - BBIN से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी आसान।

(e) इससे देशों मे सामूहिक प्रभाव
- एशिया- अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
भारत - ~~अफ्रीका~~ जापान के बीच अफ्रीका मे
एक साथ विकास करने हेतु।

अतः वर्तमान विश्व बहु-ध्रुवीय
विश्व-व्यवस्था की तरफ स्थानांतरित हो
रहा है। इससे भारत भी अब
'Non-Alignment' से Multi-Alignment
की तरफ बढ़ रहा है। ~~अतः~~
इस प्रकार मुद्दे आधारित गठबंधन
भविष्य मे ज्यादा प्रभावी होंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

भारत ऊर्जा आवश्यकता हेतु 80% से ज्यादा आयात पर निर्भर है। अतः ऊर्जा-सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा दक्षिणी एशियाई देश मिलकर इस दिशा में प्रभावी उपाय कर सकते है।

ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में संतुलन व विकास हेतु एक-दूसरे के साथ साझा ऊर्जा उत्पादन व पारेषण आवश्यक है।

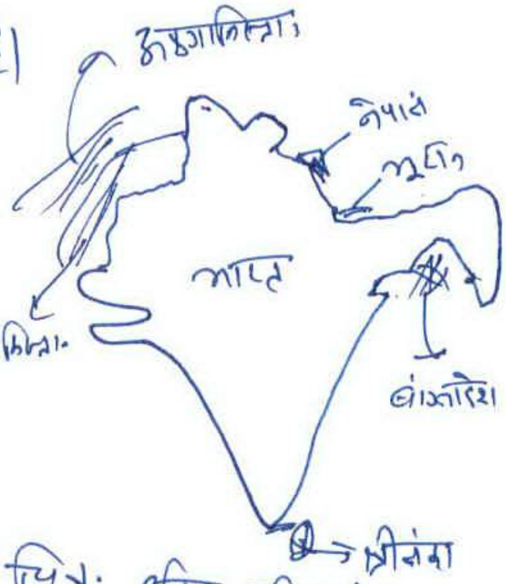

चित्र: दक्षिण एशियाई देश

सहयोग की आवश्यकता

(1) संपूरक आवश्यकताए

• गर्मी मे भारत की आवश्यकता ज्यादा है तो वह नेपाल-भूटान से ऊर्जा ले सके तथा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सदी में उन्हें जरूरत है तो भारत उन्हें दे सके।

② सौदेबाजी – ये देश एक संगठन के तौर पर आयात हेतु बेहतर सौदेबाजी कर सकते है।

③ साझा परियोजना
भारत-नेपाल, भारत-भूटान व बांग्लादेश के साथ विद्युत की साझा परियोजनाएं क्रियान्वित है। जैसे- पूजा विद्युत परियोजना

④ नवीकरणीय ऊर्जा
– आत्मनिर्भरता हेतु एक-दूसरे के साथ सहयोग से ISA के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर जोर।

⑤ SAGR जैसे पहलों के माध्यम से आपदाएँ सहयोग।

विद्यमान चुनौतियाँ

① आपसी विवाद
भारत-पाक सीमा विवाद के कारण सहयोग नहीं। जैसे ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (IPI) पाइपलाइन समझौते क्रियान्वयन नहीं

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) वित्त का अभाव - भारत के अलावा अन्य देश इस मामले में कमजोर है।

(3) चीनी फैक्टर - चीन स्वयं निवेश करके इन देशों को लुभा रहा है

(4) SAARC की असफलता - यह पाकिस्तान के रवैये के चलते प्रभावी नहीं है

समाधान → सहयोग व आपसी विश्वास के आधार पर जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करें।

→ नवीकरणीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को बढ़ावा

अतः दक्षिण-एशिया के देश चाहे तो आपसी एकता में इस चुनौती से निपटने में सक्षम हो सकेंगे तथा विकास तीव्र गति से कर सकेंगे।